नईदुनिया

अनुमानः हर महीने 7.72 करोड़ प्रति सांसद व सालाना 1350 करोड़ अतिरिक्त विकास राशि का प्रावधान

सीटें बढ़ने का असर : लोकसभा में सांसदों की संख्या 815 होती है तो खर्च भी बढ़ेगा?

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 815 करने की तैयारी कर रही है। परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव के तहत मौजूदा सदस्य संख्या में करीब 50 प्रतिशत वृद्धि का विचार है। इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए संसद का विशेष सत्र 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक बुलाया गया है। सीटें बढ़ने का असर केवल सदन की संरचना पर नहीं, बल्कि सांसदों के वेतन, भत्ते, आवास, कार्यालय, कर्मचारियों और अन्य सुविधाओं पर होने वाले सरकारी खर्च पर भी पड़ेगा।



270 नए सांसदों पर वेतन और भत्तों का खर्च

यदि लोकसभा की सदस्य संख्या 545 से बढ़कर 815 होती है, तो 270 सांसद बढ़ेंगे। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार एक सांसद को हर महीने 1.24 लाख रुपये वेतन, 87 हजार रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 75 हजार रुपये कार्यालय खर्च भत्ता मिलता है। इन तीनों मदों को मिलाकर एक सांसद पर हर महीने 2.86 लाख रुपये का खर्च होता है। इसी आधार पर 270 अतिरिक्त सांसदों के वेतन और इन दो भत्तों पर हर महीने करीब 7.72 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सालाना यह राशि लगभग 92.66 करोड़ रुपये होगी। यह गणना केवल वेतन और निर्धारित भत्तों तक सीमित है। इसमें अन्य सुविधाओं का खर्च शामिल नहीं है।

दैनिक भत्ते पर भी बढ़ेगा खर्च

सांसदों को संसद सत्र और निर्धारित संसदीय कार्यों के दौरान पात्र दिनों के लिए 2500 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। यदि 270 नए सांसदों को साल में 60 दिन यह भत्ता मिले, तो करीब 4.05 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हो सकते हैं। वास्तविक खर्च संसद की बैठकें और सांसदों की पात्रता के दिनों पर निर्भर करेगा।

विकास निधि पर भी पड़ेगा असर

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत प्रत्येक सांसद को विकास कार्यों की सिफारिश के लिए सालाना पांच करोड़ रुपये तक की राशि मिलती है। यदि 270 अतिरिक्त सांसद भी इस व्यवस्था के दायरे में आते हैं, तो सालाना 1350 करोड़ रुपये अतिरिक्त विकास राशि का प्रावधान बन सकता है। यह राशि सांसदों की निजी आय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय विकास कार्यों के लिए होती है।

आवास, कार्यालय और कर्मचारियों की व्यवस्था

सांसदों की संख्या बढ़ने पर दिल्ली में सरकारी आवास, फर्नीचर, बिजली-पानी, मरम्मत और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी होगी। नए सांसदों के लिए कार्यालय और सचिवीय सहायता की जरूरत बढ़ेगी। संसद सचिवालय, समितियों, सुरक्षा, अभिलेख और सदन की कार्यवाही से जुड़े संसाधनों पर भी अतिरिक्त खर्च हो सकता है। इन मदों का खर्च सदस्य संख्या के अनुपात में सीधे तय नहीं होगा।

परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी राकांपा : आव्हाड

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी। पार्टी विधायक जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिसीमन संवैधानिक आवश्यकता है और पार्टी इस प्रक्रिया के समर्थन में है। आव्हाड ने कहा कि शरद पवार के साथ बातचीत के बाद परिसीमन को लेकर समर्थन का निर्णय लिया।

परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस परिसीमन विधेयक का विरोध करेगी। शुक्रवार को सोनिया गांधी के आवास पर हुई संसदीय दल की बैठक में आगामी विशेष सत्र और परिसीमन प्रस्ताव को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शनिवार सुबह 11.30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक होगी। इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और शरद पवार गुट सहित अन्य दलों को आमंत्रित किया जाएगा।

लोस राजग को 40 सांसदों के समर्थन की जरूरत

परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पारित कराने के लिए राजग को करीब 40 सांसदों के अतिरिक्त समर्थन की जरूरत है। 540 सदस्यीय सदन में सभी सांसदों के मतदान की स्थिति में दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 मत जरूरी होंगे। राजग के पास करीब 320 सांसद हैं। सरकार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के आठ सांसदों का समर्थन मिलने का दावा है। इसके अलावा द्रमुक के 22 और वाईएसआर कांग्रेस के चार सांसदों से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। यूपीपीएल और जेडपीएम के एक-एक सांसद का समर्थन भी अपेक्षित है।

रास में राजग को 11 सांसदों की कमी

राज्यसभा में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए राजग को 11 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत है। सरकार के पक्ष में फिलहाल 151 सांसद बताए जा रहे हैं, जबकि विधेयक पारित कराने के लिए 161 मत आवश्यक हैं। द्रमुक के आठ, वाईएसआर कांग्रेस के चार और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के एक सांसद का समर्थन मिलने पर सरकार के पक्ष में 164 मत हो सकते हैं।

रूस ने 35 साल का सबसे बड़ा रक्षा बजट बनाया, तीन साल में खर्च करेगा 54 लाख करोड़



कुल सरकारी खर्च का 35 प्रतिशत से अधिक हिस्सा सेना पर, स्वास्थ्य और पेंशन बजट में कटौती का प्रस्ताव

मॉस्को, एजेंसीः रूस ने सोवियत संघ के विघटन के बाद अपना सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सरकार अगले तीन वर्षों में सेना पर करीब 50 लाख करोड़ रूबल यानी लगभग 54 लाख करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। इस हिसाब से रूस का औसत वार्षिक रक्षा खर्च करीब 18 लाख करोड़ रुपये होगा, जो भारत के 2026-27 के रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये से लगभग 2.3 गुना अधिक है। बजट के अनुसार, 2027 में रूस के कुल सरकारी खर्च का करीब 35.2 प्रतिशत हिस्सा रक्षा क्षेत्र पर खर्च होगा। इस वर्ष सेना पर 17.15 लाख करोड़ रूबल यानी लगभग 19.84 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। यह 2026 के निर्धारित रक्षा खर्च से करीब 33 प्रतिशत अधिक है। इसके बाद 2028 में रक्षा खर्च 16.61 लाख करोड़ रूबल और 2029 में 16.30 लाख करोड़ रूबल रहने का अनुमान है। दोनों वर्षों में खर्च पहले की तुलना में अधिक रहेगा।

यूक्रेन युद्ध में अब तक 67 लाख करोड़ रुपये खर्च

रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू किया था। इसके बाद से सैन्य खर्च लगातार बढ़ा है। शोधकर्ता जेनिस क्लुग के अनुसार, रूस अब तक युद्ध पर करीब 58.3 लाख करोड़ रूबल यानी 67.45 लाख करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। यदि अगले तीन वर्षों का प्रस्तावित रक्षा बजट भी पूरा खर्च होता है, तो 2029 तक कुल सैन्य खर्च लगभग 124 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।

स्वास्थ्य और पेंशन बजट में कटौती

रक्षा खर्च बढ़ाने के साथ रूस सरकार ने कई अन्य विभागों के बजट में कटौती का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में करीब तीन प्रतिशत, पेंशन और सरकारी सहायता में छह प्रतिशत तथा आवास और बिजली-पानी जैसी सुविधाओं के बजट में आठ प्रतिशत कटौती का अनुमान है। रूस का 2027 में बजट घाटा करीब 5.44 लाख करोड़ रूबल रहने की संभावना है, जो अर्थव्यवस्था का लगभग 2.2 प्रतिशत होगा। सरकार को कर्ज लेना पड़ सकता है।

23 नवंबर को दर्ज हुई थी शिकायत, पूर्व मुख्यमंत्री स्टालिन ने मामले को दबाने का आरोप लगाया

महिला अधिकारी को अश्लील संदेश भेजने के आरोप में टीवीके विधायक गिरफ्तार

नईदुनिया ब्यूरो, चेन्नईः तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके के विधायक अरुल विग्नेश को शुक्रवार देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विधायक पर महिला जिला अधिकारी को अश्लील संदेश भेजने और अनुचित व्यवहार करने का आरोप है। महिला अधिकारी ने 23 नवंबर को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को लेकर विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। शिकायत के बाद कल्लाकुरिची के महिला पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विधायक अरुल विग्नेश ने आरोपों को खारिज करते हुए इसे अपनी और पार्टी की छवि खराब करने की राजनीतिक कोशिश बताया था। विधायक की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आरोप लगाया



कि टीवीके सरकार ने मामले को दबाने और विधायक को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और सहयोगी दलों के नेताओं ने शिकायत को खारिज करने तथा विधायक को दोषमुक्त बताने का प्रयास किया। स्टालिन ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतकर्ता महिला अधिकारी को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए सामाजिक माध्यमों पर अपमानजनक अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारी ने दबाव के बावजूद शिकायत दर्ज कराने का साहस दिखाया।

उच्च न्यायालय ने जांच की निगरानी के निर्देश दिए

उच्च न्यायालय ने 24 नवंबर को सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्रवाई में देरी पर सवाल उठाते हुए जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराने के निर्देश दिए थे। तिरुपुर की पुलिस अधीक्षक सृष्टि सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जबकि पुलिस महानिरीक्षक स्तर की अधिकारी एन कामिनी को जांच की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुलिस ने 25 नवंबर को विधायक को पूछताछ के लिए बुलाया था। जांच के दौरान शिकायतकर्ता महिला अधिकारी और मामले से जुड़े अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए गए।

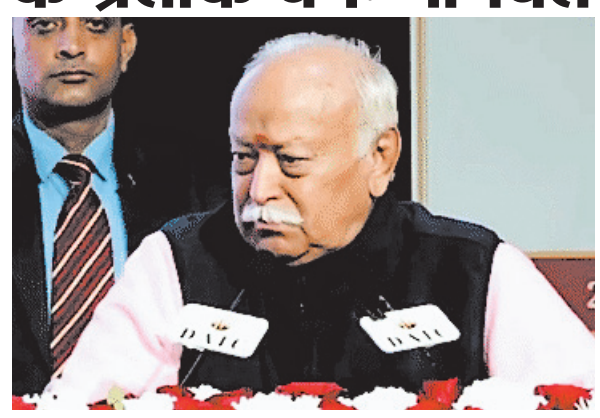
भाजपा की दो दिवसीय बैठक में संगठन विस्तार और कार्ययोजना पर चर्चा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भाजपा संगठन की दो दिवसीय कार्यशाला शुक्रवार को दिल्ली के पूसा में शुरू हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्यों के प्रभारी शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उद्घाटन सत्र में पहुंचे। कार्यशाला में संगठन को मजबूत बनाने, पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने और भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष कर रहे हैं। इस दौरान कार्यशाला का एजेंडा और लक्ष्य तय किए जाएंगे। नितिन नवीन भी प्रतिभागियों को संबोधित कर सकते हैं। रात करीब नौ बजे अनौपचारिक चर्चा का सत्र शुरू होने की योजना है, जो देर रात तक चल सकता है। कार्यशाला के दूसरे दिन शनिवार को सुबह से बैठक की कार्यवाही शुरू होगी। इस दिन तीन सत्र आयोजित किए जाएंगे।

रावण 'मैं और मेरा' में उलझा रहा राम करुणा के प्रतीक बनेः भागवत

मानव तभी सुखी होगा जब पूरा संसार सुखी हो और पर्यावरण स्वस्थ रहे

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा कि मानव जाति अकेले सुखी नहीं रह सकती। जब पूरा संसार सुखी होगा और पर्यावरण स्वस्थ व प्रसन्न रहेगा, तभी मनुष्य भी सुखी हो सकेगा। उन्होंने यह बात नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक 'करुणानायक राम' के लोकार्पण समारोह में कही। दिल्ली में आयोजित समारोह में भूटान के शाही परिवार की राजमाता और राजकुमारी भी उपस्थित थीं। इस दौरान भागवत ने धर्म, मानवीय मूल्यों, अहंकार और करुणा के संदर्भ में भगवान राम और रावण के जीवन से जुड़े प्रसंगों का उल्लेख किया। भागवत ने कहा कि जब हम महान व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन



करते हैं, तो अक्सर उनके कार्यों पर ध्यान देते हैं और उन्हें आदर्श मानते हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से भी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है।

राम और रावण के बीच अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि रावण अहंकार से भरा था, जबकि राम करुणा के प्रतीक थे। रावण को अपने बल, ज्ञान और साम्राज्य पर गर्व था। वह 'मैं' और 'मेरा' की भावना से आगे नहीं बढ़ पाया। इसके विपरीत, राम का व्यक्तित्व व्यापक था। वे केवल अपने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सबके लिए बने। भागवत ने इस उदाहरण के माध्यम से अहंकार और करुणा के बीच के अंतर को समझाया। उन्होंने कहा कि मानव जीवन में करुणा, सामूहिक सुख और व्यापक दृष्टिकोण का महत्व है। केवल स्वयं के सुख की चिंता करने से समाज और संसार का कल्याण संभव नहीं है।

ईरान की धमकियों के बाद ट्रंप के पांच मंत्री सैन्य ठिकानों पर रहने पहुंचे



निजी घर छोड़कर सुरक्षित सैन्य आवासों में रह रहे वरिष्ठ अधिकारी, चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के करीब पांच मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी निजी आवास छोड़कर सैन्य ठिकानों पर बने सुरक्षित घरों में रहने चले गए हैं। अधिकारियों ने ईरान से मिल रही जान से मारने की धमकियों और अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक हिंसा को इसके पीछे की वजह बताया है। इन सैन्य आवासों में चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था है और आम लोगों की पहुंच सीमित रहती है। विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट सहित कई अधिकारी सैन्य परिसरों में रह रहे हैं। सैन्य ठिकानों पर वरिष्ठ अधिकारियों के रहने का चलन पहले की तुलना में बढ़ा है। इनमें पहले सेना के बड़े अधिकारी और जनरल रहते थे।

एक ही परिसर में कई अधिकारी

मार्को रुबियो, पीट हेगसेथ और स्टीफन मिलर के परिवार फोर्ट मैकनेयर में आसपास रहते हैं। सैन्य अधिकारियों के लिए बने आवासों की एक कतार को जनरल्स रो कहा जाता है। इन घरों में रहने के लिए अधिकारियों को किराया देना पड़ता है, जो सामान्य तौर पर 4,500 डॉलर से अधिक होता है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के आवास की मरम्मत और सुविधाओं पर अमेरिकी सेना करीब 1 लाख 37 हजार डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रही थी। इस खर्च को लेकर सवाल भी उठे थे। अमेरिका में रक्षा मंत्री को सैन्य परिसर में आवास देने की व्यवस्था रॉबर्ट गेट्स के कार्यकाल में शुरू हुई थी। वर्ष 2008 में नियमों में बदलाव के बाद रक्षा मंत्री को चार सितारा जनरल या एडमिरल के आवास के किराये से पांच प्रतिशत अधिक भुगतान करने की व्यवस्था लागू हुई।

धमकियों के बाद बदला आवास

वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में जॉर्जटाउन स्थित अपना घर छोड़कर सैन्य ठिकाने पर रहने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि ईरान से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने और प्रतिबंध लगाने की मुहिम में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। व्हाइट हाउस के प्रमुख सलाहकार स्टीफन मिलर और उनकी पत्नी केटी भी पिछले वर्ष अपने चार बच्चों के साथ वर्जीनिया स्थित घर छोड़कर फोर्ट मैकनेयर सैन्य परिसर में रहने चले गए थे। उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था और निजी जानकारी सार्वजनिक किए जाने के साथ धमकियां भी मिली थीं।

कुलगाम में जलस्रोत और पाइपलाइन में जमने लगा पानी

कश्मीर में कड़ाके की ठंड

राजस्थान में शीतलहर का असर, 13 राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में सर्दी का असर तेज हो गया है। जम्मू-कश्मीर में तापमान लगातार गिर रहा है। गुरुवार को श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही। कुलगाम में पेड़ों की टहनियों पर बर्फ जमने लगी है। जलस्रोतों और पानी की पाइपलाइनों में भी पानी जमने की स्थिति बनी है। कश्मीर संभाग में सर्दी को देखते हुए सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व प्राथमिक से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय 30 नवंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। वहीं, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की छुट्टियां 14 दिसंबर से 22 फरवरी तक रहेंगी। राजस्थान के



22 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। राजस्थान के फतेहपुर में तापमान 4.3 डिग्री और मध्य प्रदेश के करौंदी में 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोनों राज्यों में शीतलहर का प्रभाव बढ़ने का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित 13 राज्यों में कोहरे का असर रहने की संभावना है। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। आंध्र और रायलसीमा में तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

रणनीति *हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करने की शर्त पर अरब पार्टी से गठबंधन की बातचीत*

इजराइल में सत्ता परिवर्तन की कोशिश तेज, राअम पर नजर

तेल अवीव, एजेंसीः इजराइल की राअम पार्टी के प्रमुख मंसूर अब्बास शनिवार रात हमास को आतंकवादी संगठन मानने का ऐलान कर सकते हैं। एक साक्षात्कार में वह अपना रुख स्पष्ट करेंगे। उनके इस बयान से गादी आइजनकोट के नेतृत्व में नई सरकार के गठन का रास्ता खुल सकता है।

आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए अब केवल नौ दिन का समय बचा है। आइजनकोट ने गठबंधन में शामिल होने की इच्छुक अरब पार्टियों से हमास को आतंकवादी संगठन मानने और उसके खात्मे का संकल्प लेने की शर्त रखी है। मंसूर अब्बास के इस रुख से नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए विपक्ष को बहुमत जुटाने में मदद मिल सकती है।

साक्षात्कार के प्रचार वीडियो में अब्बास ने संकेत दिया कि ऐसा बयान देने पर उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मंसूर अब्बास वर्ष 2021 से 2022 तक इजराइल की गठबंधन सरकार में शामिल रहे थे। उन्होंने सात अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की आलोचना की थी, लेकिन कभी खुले तौर पर हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया। उनका तर्क था कि ऐसा करने से अरब और यहूदी समुदायों के बीच बातचीत का रास्ता बंद हो सकता है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई थी।



बहुमत के लिए राअम का समर्थन अहम बहुमत

इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। नेतन्याहू के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं, जबकि गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के पास 48 सीटें हैं। आइजनकोट सात सांसदों वाली यूनाइटेड टोरा जूडिज्म पार्टी से भी बातचीत कर रहे हैं। उसका समर्थन मिलने पर विपक्षी गठबंधन की संख्या 55 हो जाएगी। राअम के आठ सांसदों का समर्थन मिलने पर यह आंकड़ा 63 तक पहुंच सकता है, जो बहुमत से दो अधिक होगा। इजराइल में अरब समुदाय से जुड़ी चार प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं। हदाश, ताअल और बलद संयुक्त सूची के तहत चुनाव लड़ी थीं, जबकि राअम ने अलग चुनाव लड़ा। संयुक्त सूची को 11 और राअम को आठ सीटें मिली थीं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने आठ नवंबर को आइजनकोट को सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्हें छह दिसंबर तक बहुमत जुटाना है। समयसीमा बढ़ाने का विकल्प भी है। यदि आइजनकोट सरकार बनाने में विफल रहते हैं, तो राष्ट्रपति दोबारा नेतन्याहू को मौका दे सकते हैं। दोनों नेता बहुमत जुटाने में असफल रहे तो इजराइल में फिर चुनाव हो सकते हैं।